

## RAJYA SABHA

Wednesday, the 30th November, 1977/ the  
9th Agrahayana, 1899 (Saka)

The House met at Eleven of the clock, Mr.  
Chairman in the Chair.

Oral Answers to Questions

\*301. [The questioners (Shri Deorao Patil,  
Shri R. D. Jagtap, Avergankar and Shri  
Krishnarao Narayan Dhulap) were absent.  
For answer, vide col. 39.40 infra.]

### Termination of Services of C.G.H.S. Doctors

\*302. SHRI HIMMAT SINH:  
DR. V. P. DUTT:f  
SHRIMATI HAMIDA HABI-  
BULLAH:  
SHRI JAGJIT SINGH  
ANAND:  
SHRI SAWAISINGH SISO-  
DIA:

Will the Minister of HEALTH AND  
FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have terminated  
or decided to terminate the services to  
thousands of C.G.H.S. doctors;

(b) if so, what are the details in this  
regard and what are the reasons therefor;

(c) what is the average length of service  
of these doctors under the  
CGHS;

(d) in what manner Government propose  
to fill the resultant vacancies; and

(e) what steps Government have taken to  
provide alternate employment to these  
doctors?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव):  
(क) से (इ) एक विवरण सभा पटल पर  
रख दिया गया है।

### विवरण

तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए 679  
कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। इन अधि-  
कारियों को भर्ती तथा नियुक्ति के समय स्पष्ट  
रूप से बताया गया था कि जब तक यह  
पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये  
डाक्टरों से नहीं भर लिये जाते तब तक के लिए  
यह बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था है। इनमें से  
1975 से 1977 तक के वर्षों में 400 तदर्थ  
डाक्टरों को नियुक्त किया गया था। संघ  
लोक सेवा आयोग के नियमित डाक्टरों के  
आने पर अपात स्थिति के दौरान भर्ती किए  
गए केवल उन्हीं तदर्थ डाक्टरों की सेवाएं  
समाप्त की जा रही हैं जिनके संगठनों में उन्हें  
खपाने के लिए कोई स्पष्ट खाली पद उपलब्ध  
नहीं हैं। ऐसी सम्भावना है कि 1975 से पहले  
नियुक्त कोई भी तदर्थ डाक्टर फिलहाल छंटनी  
का शिकार नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग  
से नियमित आधार पर नियुक्त डाक्टरों के  
आने से जिन तदर्थ डाक्टरों को हटना पड़  
रहा है, उनको भी फिलहाल बाहरी इलाकों में  
वैकल्पिक नौकरी की पेशकश की जा रही है।

शुरू 1978 में जिन वर्तमान रिक्त पदों को  
भरने के लिए चयन किए जाने का प्रस्ताव है,  
उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन  
निकाले हैं, उन पर ये बर्खास्त किए गए तदर्थ  
डाक्टर फिर से आवेदन कर सकते हैं।

\*[THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY  
WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD  
YADAV): (a) to (e) A Statement is placed on  
the Table of the Sabha.

### Statement

There are about 679 Junior Medical  
Officers appointed on *ad-hoc* basis

tThe question was actually asked on the floor of the House by Dr. V. P. Dutt.

t[ ] English translation.

with a clear understanding both at the time of recruitment as well as appointment that this was purely a temporary arrangement until such time as these posts were filled by regular appointees to be recommended by the Union Public Service Commission. Out of these there was an intake of about 400 *ad-hoc* appointees during the years 1975—77. The services of only such *ad-hoc* appointees who were recruited during emergency are being terminated on being replaced by regular UPSC candidates, if there were no other clear vacancies available to absorb them in the same organisation. No *ad-hoc* appointees who joined earlier than 1975 are expected to face retrenchment for the time being. Even those *ad-hoc* appointees who are displaced by UPSC nominees are being offered alternative jobs in outlying areas for the time being.

The displaced *ad-hoc* appointees can also apply afresh in response to UPSC advertisements for filling in the existing vacancies in respect of which selections are proposed to be held early 1978.]

DR. V. P. DUTT: You are well aware of the fact that some of our brightest students go into the medical profession and that they get probably the longest and the most intensive training in any profession in this country. And yet, a large number of people appointed through duly constituted selection committees on an *ad hoc* basis have been given notices of termination of their service. I underline the words 'duly constituted selection committees' that is, boards of competent experts. Therefore, it is not as if these people are below qualifications; these are people who have been trained through the norms laid down by the medical associations.

I am sorry, the hon. Minister of Health and Family Welfare is not here; he would have provided some heat, if not light. I would like to ask: Is it not a fact that the UPSC by a letter dated 18-6-77 had laid

down certain guidelines? The first part of those guidelines was—

"It has been decided that the candidates if any working on an *ad hoc* basis in your organisation in fulfilment of the bond already executed with the Government may be allowed to continue on an *ad hoc* basis irrespective of the length of the service and need not be replaced by the regular officers."

Has this guideline been already violated or not in the case of a number of people? I would also ask whether it is not a normal practice that a person is kept on probation only for one year or for a maximum of two years? Therefore, I would ask what is the number of people who are now being thrown out of jobs, who have put in more than 2 years of service and whether you are not violating your own guideline by giving them termination notices.

(Interruptions)

DR. V. P. DUTT: The hon. Minister is

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए 679 कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को भर्ती तथा नियुक्ति के समय स्पष्ट रूप से बताया दिया गया था कि जब तक यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये डाक्टरों से नहीं भर लिये जाते तब तक के लिए यह बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था है। इनमें से 1975 से 1977 तक के वर्षों में 400 तदर्थ डाक्टरों को नियुक्त किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के नियमित डाक्टरों के आने पर आपातस्थिति के दौरान भर्ती किये

MR. CHAIRMAN: He does not want that information at all.

replying even without listening to the

श्री राजनारायण : श्रीमन्, वे तो हीट चाहते हैं। मैं उनको हीट दे दूंगा . . . question.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** श्रीमन्, मैंने यह बताया है कि 1975 से 1977 तक के वर्षों में 400 डाक्टर तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे। चूंकि उन्होंने अपने सवाल में यही बात पूछी है, इसलिए मैं यह जवाब दे रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग से नियमित डाक्टरों के आने पर आपातस्थिति के दौरान भर्ती किए गए केवल उन्हीं तदर्थ डाक्टरों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं जिन संगठनों में उन्हें खपाने के लिए कोई स्पष्ट खाली पद उपलब्ध नहीं हैं। श्रीमन्, मैं यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि अभी तक जो डाक्टर हटाये गये हैं उनकी संख्या सिर्फ 16 है।

DR. V. P. DUTT: Sir, he has not answered my first question.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may reply to two supplementaries: first, whether the guidelines laid down by the Public Service Commission have been violated or not. That is what he wants to know.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** पब्लिक सर्विस कमिशन ने इसबारे में जो नियम दिये हैं, वह इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एडहोक हैं, उन सब को लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा, और उसमें उनका निर्णय किया जायेगा कि कौन लिया जा सकता है और कौन नहीं लिया जा सकता है। रिटिन एक्जामिनेशन के बारेमें लोक सेवा आयोग ने इसलिये लिखा है क्योंकि पहले साल भर में केवल 50 से 100 डाक्टर, लिये जाते थे लेकिन इमरजेन्सी में एक साल में 400 डाक्टर लिये गये। जो अप्वायंटमेंट किये गये वह हजारों की संख्या में थे। इसलिये उन्होंने रिटिन एक्जामिनेशन और ओरल दोनों लिये। इसमें सिर्फ यह बात निकली।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: What about the other question?

MR. CHAIRMAN: Please wait, I am here. Then he asked about the probationary period.

**श्री राजनारायण :** जो एडहोक अप्वायंटमेंट हुआ है, इसके बारे में सदन में पहले भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार किसी को निकालना नहीं चाहती। प्वाइंट यह है कि कुछ लोग इमरजेन्सी पीरियड में लिये गये, 400 डाक्टर लिये गये। अब हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमिशन से बात की है। वह कहते हैं कि हम एक्जामिनेशन उनका लेंगे। पहले चार सबजेक्ट में लेते थे, अब केवल एक सबजेक्ट में लेंगे। पहले सर्जरी, मेडीसन, प्रसूति चिकित्सा और रोगों की रोकथाम इन चारों विषयों पर देना पड़ता था। लेकिन इसमें उनको रियायत दी गई है। हमने कहा कि क्योंकि वे हमारी सर्विस में हैं, इसलिये हम उनको निकालना नहीं चाहते। पब्लिक सर्विस कमिशन ने इस बात को मान लिया है कि हम एक विषय में ही, जिस विषय में वे चाहे, परीक्षा दे दें। यदि पास हो जायेंगे तो उनको रखा जायेगा और यदि पास नहीं होंगे तो नहीं रखा जायेगा।

DR. V. P. DUTT: Sir, my first question was whether the guidelines have been...

MR. CHAIRMAN: That is all right.

DR. V. P. DUTT: ...violated or not. There is no answer to that.

MR. CHAIRMAN: Put your second supplementary.

DR. V. P. DUTT: Yes, I would like to...

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, ...

MR. CHAIRMAN: Let him say. It is recorded there. Why do you get up?

**डा० विद्या प्रकाश दत्त :** यदि आप चाहते हैं तो नहीं पूछता साहब, मैं बैठ जाता हूँ।

**श्री राजनारायण :** नहीं, आप पूछिये।

DR. V. P. DUTT: I was going to appeal to you to take a human view of it, and not associate it with Emergency as such.

MR. CHAIRMAN: He has already replied correctly.

DR. V. P. DUTT: I would like, firstly, to ask whether the figure given by the hon. Minister of State is correct that only 16 people have been removed. My information from all the newspaper reports is that a large number is involved. Secondly, arising from it, I would like to ask whether the normal procedure in such cases is that those who are appointed last are the first to be given termination notices. If so, is it not a fact that in a number of cases, that has been violated? I do not want to mention individual cases. In the Willingdon Hospital, there is the case of Dr. Arora. There are other cases, but I do not want to mention them. There have been violations of the guidelines and also violations in various cases of the assurances given by the hon. Minister.

**श्री राजनारायण :** श्रीमान, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सदन के सम्मानित सदस्य जब यहाँ आते हैं तो पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिये गये रहते हैं, उनको पढ़ने की कृपा नहीं करते, तकलीफ नहीं उठाते। मैं गाइड लाइन जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है, उसको बता रहा हूँ . . . . .

**श्री राजनारायण :** आप कृपया बैठिये। मैं यह कह रहा हूँ कि 'पब्लिक सर्विस कमीशन का मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए' तो इस मानवीय दृष्टिकोण की जो वकालत की है, हमारे दोस्त ने, चाहे उनका खुद मानवीय दृष्टिकोण न हो, मगर हमारी सरकार का मानवीय दृष्टिकोण है और इस मानवीय दृष्टिकोण के कारण ही जो इमरजेंसी के दौरान हुआ है, उनको हटाने के लिये वह

कहते थे कि उनको चारों परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा। हमारी तरफ से तो सब के साथ समान व्यवहार किया जाता है। एक विषय में सबको बैठना पड़ेगा, यह गाइड लाइन्ज हैं। एक विषय में अगर वे पास हो जाएंगे तो किसी को नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य दत्ता साहब चाहते हैं कि Quacks should be appointed. No. The Government is not going to appoint quacks.

DR. V. P. DUTT: Sir, on a matter of personal explanation...

SHRI RAJNARAIN: Sir, I am on my legs...

DR. V. P. DUTT: Sir, I have not made any such statement. Why is the Minister getting into the habit of imputing statement to us? I have not made any such statement.

MR. CHAIRMAN: No, no. You have not made any such statement. Now, Rajnarainji, you please reply to the question. The House is satisfied...

**श्री राजनारायण :** उन्होंने जो एक बात कही कि हजारों निकाले गए, यह मेरी समझ में नहीं आता। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सैटिसफाईड हैं, हाउस सैटिसफाईड है। आप कृपा करके एक मिनट का समय दे दीजिए और मैं सम्मानित सदस्य को सैटिसफाई कर दूँ। कहीं पर भी नहीं निकाले गए, अखबारों की गप्प पर सम्मानित सदस्य न चले। मैंने पहले बता दिया है कि ऐसे डाक्टर कुल 679 हैं जिनको परीक्षा में बैठना है अतः इससे ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हल्ला करने से कोई मतलब नहीं है। हल्ला करके, चापलूसी करके कोई लाभ नहीं है, अब इंदिरा गांधी के पास वह ताकत नहीं रह गई है . . .

(Interruptions)

**श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह :** सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछ न

चाहती हूँ कि आज ही अखबारों में यह खबर छपी है कि एक बड़ी तादाद में सीनियर स्पेशलिस्ट्स को जूनियर स्पेशलिस्ट की जगह पर रिवर्ट कर दिया गया है। यह आज ही अखबार में निकला है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि क्या यह खबर सच्ची है। खबर यह है कि :

"Over 12 specialists in four hospitals run by the Municipal Corporation face threat of reversion to lower posts. As many as 10 specialists have been reverted over the last year." They were reverted over the last one year.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, यह सवाल तो इससे संबंधित नहीं है। जूनियर सीनियर की बात नहीं है। इसके लिए अगर एक दूसरा नोटिस दे दें तो इसकी सूचना...

MR. CHAIRMAN: Not that, she just wanted to know whether it is not the practice that the person who comes first should be the last to go or the person who comes last should go first. There is no need for a separate question. Have you any information or not?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप समझ गए, सारा सदन समझ गया कि हमारे यहां लास्ट शुड गो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल नहीं चलेगा। हमारे यहां तो प्रिंसिपल यह चल रहा है कि जो लोग परीक्षा में बैठेंगे वे परीक्षा में पास हो जाएंगे चाहे कोई लास्ट हो या फर्स्ट हो, किसी को नहीं निकाला जाएगा।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, our first difficulty is that things appear first in the newspapers and then statements are made. It was reported in all the newspapers that thousands of doctors were being thrown out. Now the Minister says, 'No'. Then, why did he not contradict the Press report earlier? Now a new thing has appeared and the Minister does not seem to know that. I would only request the honourable Minister to read the report which appeared in the Press today and then clarify what the

situation is. And that is the point which the lady Member has asked. Sir, what does the Minister say in the printed answer supplied at the Table? He says 679 were recruited and they were—on an *ad hoc* basis. They were all on a purely temporary basis. Amongst them the services of 400 who were recruited during the Emergency are being terminated. I am going by what they have said in the statement. Now my question is this. There were many misdeeds done during the Emergency. I would be one with the Minister in condemning those misdeeds. If during the Emergency these appointments were made by-passing all norms, by-passing the guidelines, by-passing the experience which the people got, by-passing the duration of probation that they worked on, then, instead of all those who were appointed, that is, instead of all the 679, why are only 400 appointed during the Emergency—being discriminated against? I would request the honourable Minister kindly to tell us what the urgent necessity was for such purely temporary appointments for which they are now being told that their services would be dispensed with. When there is such a dearth of qualified doctors in our country, why should these doctors not have been absorbed? And then, in the statement the Minister says, "Even those *ad hoc* appointees who are displaced by UPSC nominees are being offered alternative jobs in outlying areas for the time being". So, there is a definite sign of discriminatory behaviour just because emergency was involved. What was wrong with the emergency is being sought to be maintained and this is a negative attitude.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपने पहले ही संकेत कर दिया कि सदन समझ गया। मगर हमारे सम्मानित सदस्य पता नहीं क्यों उसको रिपीट कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ मान लीजिए कि पब्लिक सर्विस कमिशन परीक्षाएं लेता है।

और उससे परीक्षा में पास डाक्टर्स निकालकर आते हैं तो उनको हम कहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर हम उनको रखेंगे तो वह प्रिंसिपल वहां एप्लाइ होगा या नहीं कि last come should go first. अगर वह होगा तो इमरजेंसी के अन्दर जो भर्ती हुई है तो लास्ट निकालने की बारी उनकी आयेगी। मगर हमारी ओर से कोशिश हो रही है ऐसी व्यवस्था की कि किसी को न निकालना पड़े। परन्तु अगर निकाले जाये तो हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं।

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: It has been said that out of these, there was an intake of about 400 *ad hoc* appointees during the year 1975—77 and the services of only such *ad hoc* appointees who are recruited during the emergency are being terminated. In fact it has been reported to us that the services of so many who do not come under this category are also being terminated. Another thing is that in a letter of the Ministry of Health and Family Welfare it has been said;

"It has been decided that the bonded candidates, if any, working on *ad hoc* basis, in your organisation, in fulfilment of the bond already executed by them with the Government, may be allowed to continue on *ad hoc* basis irrespective of their length of service...."

But I find that some of the Doctors whose period of bonded service has not been completed are also being asked to go away. Therefore, I would like the Minister to tell me whether, if such specific complaints are reported to him personally, he will take the trouble of seeing that such Doctors are retained in service.

श्री राजनारायण : श्रीमान् माननीय सदस्य ने अपना जो सवाल किया उसका उत्तर भी खूद अपने से ही दे दिया। देखा जाय कि पहले जो सामान्य लोगों के मस्तिष्क में बात

है कि जो आखिर में भर्ती हो पहले निकाला जाय, उसके मुताबिक जो एक जनरल सरक्यूलर गया, मगर हम लोगों की यह बराबर कोशिश रही कि ऐसी स्थिति हो कि उनको भी न निकालना पड़े। इसलिए हमने दूसरी बात यह की कि उनके कुछ टर्म्स हैं जो उन्होंने भरे हैं, कुछ कंडीशन्स पर दस्तखत हैं, अगर उनके दस्तखत हों भी फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमिशन से मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था निकाले जिससे कि उनको खपाया जा सके।

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: The Public Service Commission will take another two or three years and by that time they will be thrown out and they will lose all their services.

श्री राजनारायण : एक बात सदन को समझ लेनी चाहिए कि यह हमारा ही मंत्रालय ऐसा है जो पब्लिक सर्विस कमिशन से करीब दूसरे तीसरे विषयों पर भी बात करता है। उन्होंने एक व्यवस्था बना दी है कि जल्दी से जल्दी वह परीक्षा करने जा रहे हैं विदिन 2-3 मन्थस। जो हमारी बात हुई चेयरमैन से उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो यह जल्दी से जल्दी होगी। मगर हमारे सम्मानित सदस्य इस बात को माने हुए हैं कि जो आखिर भर्ती हुआ है अगर जाना ही होगा तो वही पहले जायेगा। (Interruptions) और हर जगह हम लोगों ने रैफल क्ल दूसरी जगह सारे रास्ते निकाल लिए (Interruptions) अब हमारे लर्नेड एक्स सेक्रेटरी जो खड़े हुए हैं उनको मौका दीजिए।

SHRI B. N. BANERJEE: My question is very simple. Am I correct in understanding that the policy of the Government and particularly of the Health Ministry is that none of the *ad hoc* appointees should, as far as possible, be thrown out and their decision is that if any of these per-

sons, whether recruited before or during the emergency, pass in one of the subjects as decided in consultation with the Public Service Commission, they are quite safe? I think they are quite safe and their services will not be terminated. Is my understanding correct?

**श्री जगदम्बो प्रसाद यादव :** आपका सोचना सही है इसलिए मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि 4 विषयों में से अगर एक विषय में भी पास हो जाते हैं, चाहे कोई भी, तो उनको रख लिया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा।

DR. M. M. S. SIDDHU: Sir, I thought that the main interest of the House would be the care of the patients rather than of the doctors in service. Do you want a better type of doctors or a doctor who does not fulfil the conditions laid down? Sir, I am also a Member of the Medical Council of India and we know that there are institutions in which the standards are not satisfactory. Now, this being the case, may I ask the honourable Minister whether they would give them another chance to appear in the examination, I mean, those people who have not been selected, so that they have a chance to refresh their knowledge? Secondly, Sir, may I also request the honourable Minister to lay the comments of the team of experts who have interviewed them so that the House may be enlightened on the knowledge that these candidates possess? I have information with me from one of the persons who was there as an expert that some of the candidates or students were not quite up to the mark.

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion for action which the Ministry may consider. Mr. Rajnarain, you need not reply.

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, उनकी एक बात का जवाब दे दूँ। माननीय सदस्य चूँकि डाक्टर भी हैं और वे डाक्टरी पेशे में कुशल

हैं, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की अनेक कमेटीयों से भी संबंधित हैं, दिल्ली के अस्पतालों की देखरेख की कमेटी उनकी सदारत में बन रही है, उन्होंने बहुत सही कहा है कि बहुत से डाक्टर अपटु द मार्क नहीं हैं। उनको इसकी जानकारी है। मगर एक मानवीय दृष्टि है, और वह मानवीय दृष्टि डाक्टर के लिए भी होगी, रोगी के लिए भी होगी, कि ऐसा डाक्टर न रहे कि जो रोगी की दवा करके मार ही डाले। तो दोनों तरफ से हमारी मानवीय दृष्टि है।

श्रीमन् एक और सूचना दिए देता हूँ जो मेरे पास अभी आई है, कि पब्लिक सर्विस कमिशन ने हमारे दफ्तर को सूचित कर दिया Examination for selection in the month of March-April, 1978

लिया जा रहा है, ताकि उनका कौतूहल शांत हो।

MR. CHAIRMAN: Next question.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir many doctors have been penalised..

MR. CHAIRMAN: That is all right I have called the next question.

**श्री राजनारायण :** चेयरमन साहब, आप श्रीमती अम्बिका सोनी से कह दें वे खुद हमारे यहां कार्यालय में आ जाएं और जानकारी लें।

**श्रीमती अम्बिका सोनी :** आ जाऊंगी।

#### Outstanding bills of contractors pending with the DDA for payment

\*303. SHRI PIARE LAL KUREEL URF  
PIARE LAL TALIB: SHRI  
JAGDISH JOSHI: SHRI  
IBRAHIM KALANIYA: SHRI  
KHURSHED ALAM KHAN:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at present outstanding bills of contractors

fThe question was actually asked On the floor of the House by Shri Jagdish Joshi.